



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1990/आषाढ़ 18, 1912

No. 386'

NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1990/ASADHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1990

का.पा. 547(ध) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित  
ग्राहण संवैधानिकी की जाती ही के लिये प्रकाशित किया जाना है—

ग्राहण

श्री राम शरण यादव (जिन्हे इसमें इस ग्राहों “निर्वाचित सदस्य” कहा गया है) का निर्वाचन, जो जून, 1977 में विद्वार विधान सभा के लिये  
हुए भाग्यालय निर्वाचन में 241-वोड़े विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में  
निर्वाचित सदस्य थे, पटना उच्च न्यायालय द्वारा योक प्रतिनिधित्व  
प्रधिनियम, 1951 द्वारा (जिसे इसमें ग्राहों उच्च प्रधिनियम कहा गया) है  
धारा 123 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचित अध्यर्थी द्वारा छोड़  
आवरण किये जाने के याद्वारा पर 10 अप्रैल, 1980 को ग्राहस्त कर  
दिया गया था।

निर्वाचित अध्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समझ अपील फाइल  
की गई और उक्त न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश का प्रबंधन  
25 अप्रैल, 1980 को रोक दिया।

उच्चतम न्यायालय ने इसके धारा 30 अप्रूवर, 1984 को अपील  
निर्वाचित कर दिया और रोक आदेश भी हटा दिया।

निर्वाचित अध्यर्थी का मामला सचिव, विद्वार विधान सभा द्वारा  
लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1961 की धारा 8क की उपधारा (1)  
के अनुसार 19 मार्च, 1990 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया;

राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के  
अनुसार में इस प्रश्न पर ग्राहों की राय मारी है कि धया निर्वाचित  
अध्यर्थी को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना  
नाहिये और यदि हाँ, तो कितनी अवधि के लिये निरर्हित किया जाना  
नाहिये;

निर्वाचित ग्राहों ने अपनी राय (देखिए उपावन्ध) दी है कि  
निर्वाचित अध्यर्थी को उस वर्ष की अवधि के लिये निरर्हित किया जाना  
नाहिये जिसकी गणना 30 अप्रूवर, 1984 से प्रारंभ, उच्चतम न्यायालय  
के निर्णय की तारीख से की जानी चाहिये;

ग्रन मैं धारा बैक्टरामन, भारत का राष्ट्रपति उक्त प्रधिनियम की  
धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अधिकारी का प्रयोग करते  
हुए इसके द्वारा वह विनिश्चय करता है कि निर्वाचित अध्यर्थी को

30 दिसंबर, 1984 से, छह वर्ष की प्रवधि के लिये निरहित किया जाना नाहिये।

राष्ट्रपति भवन,

भारत का गालिनि

नई दिल्ली,

नवीन 3 जून, 1990

उपबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग के समझ

मंगल-विहार विधान सभा के सिये 1977 में हुए साधारण निर्वाचन में निर्वाचित श्री राम शरण यादव की निर्गत्ता।

गत

1.1 यह भारत के राष्ट्रपति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे 1951 का अधिनियम कहा गया है) की बारा 8क के अधीन निर्देश है। यह संविव, विहार विधान सभा (जो उक्त बारा के अधीन विनियित प्राधिकारी है) द्वारा उक्त बारा के अधीन नारीख 19-3-1990 की रिपोर्ट के अनुसार में 27-3-1990 को किया गया था और यह निर्वाचन आयोग की इन प्रश्न पर राय प्राप्त करने के लिये है कि यह श्री राम शरण यादव जो विहार विधान सभा के लिये 1977 में हुए साधारण निर्वाचन में निर्वाचित हुए थे, को निर्गत्ता किया जाना चाहिये और यदि तो तो फिरनी प्रवधि के लिये।

1.2 जून, 1977 में हुए साधारण निर्वाचन में 241-गोह सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये श्री राम शरण यादव को निर्वाचन पड़ना उच्च स्थायालय द्वारा नारीख 10-4-1980 के उम्मेके अद्वेष द्वारा इस आधार पर अग्रहन कर दिया गया था कि उहाँने 79-मुर्कुंडा बूथ पर आशा 123(2) (यन्वित प्रभाव) के अधीन अप्त अवधारण किया था।

2.2 पठना उच्च स्थायालय के निर्णय में निम्नलिखित उदरण की गया प्रणाली यादव द्वारा किए गए अलंकारण पर पृष्ठ का से विवरण है:-

“इन प्रकार मैंने प्रश्नान्वयों द्वारा 79-मुर्कुंडा बूथ के मंडप में दिये गये सौंचिक और बन्नावेंडी साथ की परीक्षा की है और उप पर उपर चर्चा की है जिसमें यह स्पष्ट है कि अभिन्नीय शर्जीवार का मामला सिंड करने के लिये अलंकारक साथ है कि अनशनों की नारीख को यात्रा 11-30 पूर्वाह्न तक प्राप्ती में 6 राम शरण यादव आगी जीप में मुर्कुंडा बूथ पर पहुँचे और आपने शारीरिकों में गतवास के स्थान के लिये से पछाल की। राम इकाईमार के राम प्राप्तार यादव ने उन्हें बताया कि बूथ पर उक्ते पक्ष में कम मतदान हो रहा है और उस प्रत्यर्थी में 6 राम शरण यादव ने अपने प्रादमियों द्वारा मतदानों को, जो मनदात बूथ के आधारमय थे, मतदाताओं को भव्यतीत करके वृथ पर कहा दिया और बूथ को बैर देने पर भी यादेण दिया और उक्त यादेण देकर यह बूथ में चले गये और उपरे पांचात् उक्ते कार्यकर्ताओं और गमधर्मों द्वारा बूथ को बैर दिया और मतदाताओं को भव्यतीत किया और उपरे आपने गताधिकार में वर्चित किया और अप्तर्यामी को भी देने किया और वही रोक दिया और यह इस संबंध में प्रत्यर्थी में 6 की ओर से प्रस्तुत प्रत्यक्ष और प्रविष्टसारीय साक्ष में कहीं भी विपारित नहीं होता है। अत यह अभिन्नीयरित किया गया है इस प्रत्यर्थी में 6 और उक्ते कार्यकर्ताओं ने मुर्कुंडा बूथ पर मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मत देने के स्वतंत्र निर्वाचन प्रधिकार में लेइक्षाट करके अन्वित प्रसाद का अप्त अवधारण किया है।”

(ठाकुर मुनेश्वर नाथ निह बतामध्याम नंदन मिश्र और मन्त्री- 65 एवं भारपृष्ठ 223, पृष्ठ 233 पर)

2.2 श्री राम शरण यादव की अपील पर उच्चतम स्थायालय ने नारीख 25-4-1980 के अपने आदेश द्वारा निम्नलिखित जर्नी पर मृच्छना तामील होने तक एक परीप रोक मंजूर किया।

“विहार राज्य में आपने विधान सभा निर्वाचन की दृष्टि से श्रीर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हम उच्च स्थायालय के आदेश के प्रत्यर्तन पर रोक लगाते हैं किन्तु आगामी निर्वाचन में अर्जीवार (अर्जीत श्री राम शरण यादव) का भाग लेना हम अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगा।

यह रोक आदेश उच्चतम स्थायालय द्वारा 6-5-1983 की अपील के अन्तिम निपाटन लंबित होने तक के लिये पूट कर दिया गया। 30-10-1984 को उच्चतम स्थायालय ने अपील आविज्ञ कर दिया और रोक आदेश हटा दिया। उच्चतम स्थायालय ने यह मत व्यक्त किया कि:

“माध्यमीपूर्वक लाक्षण्यों का अवशोकन करने और चर्चा के पश्चात् हम उच्च स्थायालय द्वारा निकाले गये निष्कार्य में पूर्णतया गहमत है और यह अभिन्नीयरित करते हैं कि कोई कारण नहीं है कि उच्च स्थायालय के निर्णय में कोई लेइक्षाट की जाये जिसमें कि भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा सके। हमारी राय में यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ दो मत मंजूर हैं जिसमें तो गपीलार्थी (श्री राम शरण यादव) का वंदेह का लाभ मिल जाए।”

(राम शरण यादव बनाम ठाकुर मुनेश्वर नाथ निह श्रीर मन्त्री- 6 प्राई आर 1985 एवं भी पृष्ठ 24, पृष्ठ 28 पर)

2.3 उच्चतम स्थायालय द्वारा 30-10-1984 को उपरोक्त रूप में श्री राम शरण यादव की अपील आर्जित होने और रोक आदेश हटा दिये के परिणामस्वरूप पठना उच्च स्थायालय का आदेश जिसमें श्री राम शरण यादव को अप्त अवधारण का दोषी पाया गया था, उक्त नारीख से प्राप्ती हुआ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की बारा 8क के अनुसार श्री राम शरण यादव का मामला मविष, शिक्षार विधान सभा द्वारा जो उस बारा के अधीन विनियित प्राधिकारी है, उक्त नारीख के पश्चात् “यथा शक्यव्याप्ति” प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। उक्त बारा 8क की उपाधा (1) इस प्रकार है:

“(1) बारा 89 के अधीन किसी आदेश भरा अप्त अवधारण के दोषी अतारये गये प्रत्येक अधिनियम का मामला, उस प्रावेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्ति गीद्ध, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केंद्रीय मरकार इस निम्नित विनियित करे, इन प्रश्न का अवधारण करने करने के लिये राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जावेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निर्वित किया जाये और क्या यह किया जाये सो किसी कालावधि के लिये।

परन्तु यह कालावधि जिसके लिये कोई व्यक्ति इस उपाधा के अधीन निर्वित किया जा सके, किसी भी दशा में उस नारीख से छह वर्ष में अधिक नहीं होनी जिसकी धारा 99 के अधीन उसके संवंध में किया गया था आदेश प्रभावशील होता है।

छह वर्ष की प्रवधि जिसका उपलेख उपाधा के परन्तु के लिया गया है, प्रकृत्यर, 1990 को समाप्त होगी। इसमें गोक्षव, विहार विधान सभा की ओर से सप्ताधारण विलंब किया गया है। मामले के इस प्रकृत्यर की पृष्ठक रूप में श्रान्तीय की जानी चाहिए और भावाल्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये उक्त धारा 89 के अधीन प्राधिकारियों द्वारा लंबित मामलों के बारे में राष्ट्रपति मध्यवालय या निर्वाचन प्राधिकार को कालिक विवरणी भेजने को प्रणाली असंभव करने और उसके बारे में अनुसारक गोपने के भार में विचार किया जा सकता।

3.1 आधीयोग के पास वर्तमान निर्देश प्राप्त होने के कुछ दिन के भीतर हैं, आधीयोग ने 1-4-1990 को श्री राम शारण यादव को व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्राधिकृत काउंसिल के साधारण से उपस्थित होने के लिए सुचना जारी की ज्योतिक आधीयोग सतत सिद्धांत और प्रथा के रूप में नीतिगत स्थाय के सिवायों के पालन के लिए 1951 के प्राधीनियम की धारा 8 के प्रधीन निर्देश मामलों में प्रभावित व्यक्ति की व्यक्तिगत मनवाई के लिए अवृम्म प्रवान करता है।

3.2 भी यादव आयोग के समझ 17-4-1990 को उपस्थित हुए प्राप्त वापसी वापसी तक मुनबाई स्थगित करने की प्रार्थना की। उम्होने निवेदन किया कि उन्हें आयोग की सूचना केवल एक विन पहले अर्थात् 16-4-1990 को प्राप्त हुई और वह काउंसेल नियुक्ति के लिए धन जटाने लेते तथा काउंसेल नियुक्त करने के लिए पर्याप्त समय बचाने थे। उन्हें युक्तिमुक्त समय देने की दृष्टि से मुनबाई एक मास तक स्थगित करके 16-5-1990 के लिए रखनी गई।

3.3 श्री यादव ने 15-5-1990 को लिखित निवेदित प्रस्तुत किया आर 16-5-1990 को ग्रामीण के समक्ष उपस्थित हुए और इस आधार पर कि जिस काजसेल को अहं नियुक्त करना चाहते हैं, वह किसी महत्वपूर्ण मामार्थ में वर्णन उच्च न्यायालय में अप्स्त है, मुनवाई पुनः स्थगित करके 26-5-1990 को को जाने की प्रार्थना की। ग्रामीण ने पुनः उनकी प्रार्थना, स्वीकार कर श्री आर. मुनवाई 26-5-1990 के लिए स्थगित कर दी।

३.४ श्री यादव २६-५-१९९० को आयोग के समझ पुनः प्रस्तुत था। उनका प्रतिनिधित्व श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, ज्येष्ठ अधिकारी ने किया और उनके सहायक के स्पष्ट में श्री उदित नारायण सिंह और श्री अरविंद उज्ज्वल मिश्र अधिकारी थे।

४ तारीख १०-५-१९९० को काइस किए गए लिखित निवेदन में श्री राम शरण यादव ने कहा है कि वर्ष १९८० में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उन्होंने २११ गोह विवाहन सभा निर्बन्धन धोख से नौन विवाहन मध्ये और उन्हें दो बार प्रथमेत् १९८० और १९९० में निर्विधित घांपित किया गया । उन्होंने यह भी प्रतिक्रिया किया है कि उच्चतम न्यायालय ने, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, १९५१ की धारा ९९ के अधीन ऐसा कोई ग्राहक पारित नहीं किया है जिसके आधार पर उन्हें उक्त प्रधिनियम की धारा ४३ के प्रधान निराहित किया जा सके । उन्होंने यह भी कथन किया है कि उन्हें विवक्षित महमति पद के मध्येन सकौन्त्री प्राद्धार पर प्राप्त आवरण का दोषी पता गया थीर उनकी अपील को स्थानित करते हुए उच्चतम न्यायालय ने नरस रुख प्रपनाया क्योंकि उनके विरुद्ध खाने के भाग में प्रधिनिर्णय नहीं किया । श्री यादव ने यह भी कहा कि तारीख १०-६-१९८८ की द्वारा निवाहन के पश्चात् तेरह वर्ष भीत भुक्त हुए ग्राम लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, १९५१ की धारा ४३ के अधीन छह वर्ष की निरहूता की प्रधिकतम प्रथम भी अक्तूबर, १९९० में समाप्त हो जाएगी । सदनुसार उन्होंने आयोग में कार्यवाही को रोक देने के लिए अनुरोध किया है ।

। नारायण 36-5-1990 को बूर्झ मुनवारू में थी के पा. मिह, अर्डेच प्रधिवक्ता ने श्री यादव द्वारा प्रस्तुत लिखित निवेदन की अनुरूपी की ओर युछ अतिरिक्त निवेदन भी किए वर्ष 1980, 1985 और 1990 में उसी गोद निवाचनक्षेत्र में श्री रामशरण यादव द्वारा निवेदन लड़े जाने की जावत थी के पा. सिह अर्डेच प्रधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि यद्व श्री यादव ने 1985 में निवाचित लड़ा था तब उनके नामनिवेदन की बाबत इश प्रायाश घर आपत्ति की गयी थी कि वह निरहित हो गए थे क्योंकि उम समय तक उच्चतम स्थायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था और उक्त आपत्ति को रिट्रिव आफिलर ने नामजूद कर दिया और यह कि उसके बाद श्री यादव की निरहिता की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण नहीं उठाया गया । उन्होंने निवेदन किया कि उसको ध्यान में रखते हुए श्री यादव इस सद्भाविक विषयास पर कार्य कर रहे थे कि ता. 10-4-1980 के उच्च स्थायालय के प्राप्त था ता. 30-10-1984 के उच्चतम स्थायालय के प्राप्त के प्राप्त पर बूर्झ विश्वास उग पर

प्रधिरोपित नहीं रही गयी। इस संबंध में श्री सिंह ने 1951 के प्रधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के उपबंधों के प्रति निर्देश किया जिसमें यह परिक्रियत है कि अष्ट आचरण दोषी प्रत्यक्ष आकिं को यथारिति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रभावी होने के पश्चात् यथासंवयीक्षा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह निवेदन किया कि गणराष्ट्रपति के समक्ष श्री यादव के मामले वो प्रस्तुत करने में हुआ अनुचित विवेद, श्री यादव के विरुद्ध निरहृता प्रधिरोपित नहीं करने के लिए पर्याप्त आधार है, जो मैं इस भव्याविक विषयालय पर कार्य कर रहे कि वह निरर्हित नहीं रहे और उन्होंने, 1985 और विशेष रूप में 1990 में मिर्चबन्द लड्डने में ग्रस्ताधिक भाँति, समय, श्रम और धन का अध्ययन किया। श्री सिंह ने यह भी निवेदन किया कि 1951 के प्रधिनियम की धारा 8क (1) के उपबंधों के अधीन, वह प्रधिकरण अवधि जिसके लिए निरहृता प्रधिरोपित की जा सकती है, विसी अक्षिक्षा को अष्ट आचरण का दोषी ठहराने के न्यायालय के आदेश का तारीख से छह वर्ष थी और यह कि यदि मामला राष्ट्रपति के समझ समय से प्रस्तुत किया गया होता और उनके द्वारा विनियिक्त कर दिया गया होता तो श्री यादव पर निरहृता की ग्रस्ताधि, यदि कोई होती, ग्रन्थ सक प्रवाप्य समाप्त हो गयी होती। उन्होंने इस निवेदन को पुनः बोहराया कि उच्चतम न्यायालय ने हजारा नरम रख अपनाया कि उसमें श्री यादव के विरुद्ध खर्ची प्रधिनिर्णय नहीं किया, यथा: प्राप्तोग यों भी इस मामले में नरम रख अपनाना चाहिए।

5. 2 भ्रंत में थी मिहू ने उच्चतम न्यायालय की सारीख 30-10-84 की छिकी के प्रति निर्वैष करते हुए यह उल्लेख किया कि छिकी से ऐसा प्रतीत क्षुगा कि उच्चतम न्यायालय ने ता. 6-5-1983 के न्यायालय के आवेदन को रोक किया । यद्यपि कि उच्चतम यह स्वीकार किया कि उनके पास यह विश्वास करने के लिए कोई वस्ताविक नहीं था तो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले घेतरिम आवेदन पारित किया गया था या नहीं उनकी यह दलील थी कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा 6-5-1983 को रोक आवेदन मंजूर किया गया था तो उच्च न्यायालय का आवेदन निर्वैष से भी अधिक समय के लिए प्रवृत्त रक्षा और यदि उस अवधि की भी मंगणिन किया जाए तो छह वर्ष की वह अधिकतम अवधि जिसके लिए निर्वैष अधिरोपित की जा सकती थी, पहले ही समाप्त हो गयी ।

6.1 मैंने तारीख 20-5-1990 को हुई मुनाशाद में श्रीरामशरण नाड़ी के द्विधियों के द्वारा उन्होंने और से श्री के ० पाँ० सिंह ज्येष्ठ अधिवक्ता के लिये उन्होंने पर साधारणी पर्वक विभार कर दिया है।

6.2 यद्यपि पहले में तकनीकी प्रकृति के दो प्रकारों को निपटाना आहुतगा । इनमें से एक श्री यादव के लिखित निवदन में प्रोग्राम के पी. सिंह अपेक्षितका द्वारा उठाया गया है ।

6.3 श्री यादव ने अपने लिखित निवेदन में पहुंचनी वाले का कि उच्चतम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम की धारा ४९ के अधीन कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया था जिसके आधार पर उन्हें 1951 के अधिनियम की धारा ४९ के अधीन निहित किया जा सके। इस प्रयत्न को उनके बाउसेल श्री के. पी. मित्र ज्येष्ठ अधिकारी ने 26-५-1990 की मुनावई में सही छेंगे से प्रस्तुत नहीं किया। पटना उच्च न्यायालय ने श्री यादव को भाट आवण का दोषी पाया और 1951 के अधिनियम की धारा ४९ के अधीन उस प्रमाण आरेण पारित किया। पटना उच्च न्यायालय के इस आरेण पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया और उस रोक आवेदन की तरीख 30-१०-१९८१ के उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा हटा दिया गया और तब 1951 के अधिनियम की धारा ४९ के अधीन पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया गया आदेश प्रभावी हुआ।

6, 3 श्री के. पी. मिहू ज्याष्ट अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तकनीकी प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के रोक और निर्गुणी अधिकारी प्रवाध ग्र ताके भगवत् संभवित दृ. । न्यायालय दृ. ग्र.

के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय के आदेश को, तारीख 25-4-1980 को किए गए शाने प्रतिरिद्ध आदेश द्वारा रोक दिया हो तथापि यदि तारीख 6-5-1983 को न्यायालय द्वारा पहली तारीख द्वारा आदेश भंजूर किया जाता तो भी उससे दियति में कोई संतरण नहीं था क्योंकि 1951 के अधिनियम की धारा 1(1)(b)(3) अन्य आदेश के साप्तनाम यह स्पष्ट रूप से कार्य है। अब जब उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी उच्च न्यायालय के प्रादेश को स्थानांतरित किया जाता है तो उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में वह समझा जाएगा कि वह कभी भी प्रभावी नहीं हुआ। अतः हालांकि तारीख 10-4-1980 के उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6-5-1983 को रोक लगा दिया, उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में वह समझा जाएगा कि वह कभी भी प्रभावी नहीं हुआ और तारीख 10-4-1980 का उच्च न्यायालय का आदेश, तारीख 30-10-1984 से प्रभावी बुआ समझा जाएगा जब उच्च न्यायालय ने अपील आरिज कर दी और उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दिया और रोक को दूर किया। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 1951 के अधिनियम की धारा 8(1) में विवरित छह वर्ष की अवधि, इस मामले में तारीख 30-10-1984 से संगणन की जाएगी।

7.1. जहां तक श्री यादव के लिखित विवेदन का संबंध है जिसमें उन्हें “विवरित सम्मति” पद के अधीन तकनीकी आधार पर भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था, उसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने इस निष्कर्ष के प्रति निर्वेण पर्याप्त है कि यह ऐसा भास्माना नहीं है जहां दो भूत संभव हों, जिससे कि श्री यादव को संवेदन का लाभ दिया जा सके।

7.2. श्री यादव का विवेदन, जिसे कि श्री के. पी. मिहू, जेट्ट अधिकारी ने दोहराया है, अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने श्री यादव पर कोई खाचा अधिनियम्त न करके नरस रुद्र अपनाया है, उस पर अब विचार किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने शाने निर्णय में अपील को आरिज करने के कोई कारण, खार्जे के बारे में आदेश किए विना, नहीं बताए हैं। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को स्पष्टतया और अतिरिक्त रूप से माना है। इसके अतिरिक्त, निर्णय के आरंभिक भाग में, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं यह संप्रेक्षण किया है कि “यदि भ्रष्ट आचरण का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए निर्धारित सबसे बड़ी जास्ति है।” इस संप्रेक्षण में यह प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने खांसे श्री यादव के विरुद्ध कोई खाचा अधिनियम्त नहीं किया। किनीं भी वश में उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल खांसे अधिनियम्त न करना श्री यादव के पश्च में पर्याप्ति की कम होना कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7.3. अस्ति में सत्यित, विहार विधान मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति को मामला और उससे संबंधित अस्ति विवेदन प्रस्तुत करने में हुए, अत्यधिक विलंब के बारे में कहा जाहूँगा। यह सही है कि मनिकर्ण की ओर से श्री यादव का मामला राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ है। 1951 के अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार निस्संदेह रूप से संविद से अपेक्षित है कि वह समझने का अंतिम प्रस्तुत करें। किन्तु संविद की ओर से इस बाध्यता का अवधि यह नहीं लगाया जा सकता कि वह ऐसी समय सीमा का उपर्युक्त करती है जिसके बासर मामले प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री यादव ने प्रणालीक मर्मानी की ओर से हुई इस खूक का पूरा लाभ उठाया है। वर्त यह मामला समय पर राष्ट्रपति के समझ प्रस्तुत किया गया होता तो, श्री यादव 1984 के अन्त तक या 1985 के आरंभिक भाग में ही संविद विरोहन हो गए होते। यदि उक्त धारा 8(1) में कथित पूरे छह वर्ष की निर्देश द्वारा प्रबंधि उन पर अधिरोपित की गई होती तो वे न तो 1985 में अन्त तो 1980 में निवारन लड़ने बोग्य रहते। यहां तक कि जब उन्होंने 1980 गे एकपक्षीय रूप आदेश प्राप्त कर लिया । भी 1980 जून मिर्जान लड़े तो भा वह इस बात में धूमगता अवधिन के लिये

में उसका भाग ऐसा उच्चतम न्यायालय के समझ अपील के अंतिम परिणाम के अत्यधीन होगा। उन्होंने 1980 का निवारन अपने विर द्वारा निर्धारित जीर्णी लटकती हुई तत्वावार के नींव लड़ा या क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 25-4-1980 के एकपक्षीय गोप आदेश में यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी। जब वे 1985 में निवारन लड़े, तब उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के आधार विर द्वारा नामजूर की गई थी, तो उसका एकमात्र कारण उस समय श्री यादव के विरुद्ध किसी निर्धारित आदेश का ध्यान न होना था इस बात की ध्यान रखने के बिना श्री यादव ने रखते हुए कि श्री यादव ने पटना न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपना मामला पांच वर्ष से अधिक तक लड़ा और इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए यह विवाय करना कठिन हो जाता है कि श्री यादव इस पूरी सुसंगत अवधि के दीरात कभी भी निरहित होने की संभावना से अवगत न रहे हैं। प्रक: इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित नहीं कि उन्होंने जोखिम रखने हुए 1980 का निवारन लड़ा भीर बैठी ही जोखिम रखने हुए 1985 और 1990 के निवारन पहुंचे। 1985 और 1990 के निवारन यदि वे लड़े तो तो उसका एकमात्र कारण मनिकर्ण विहार विधान मंडल की ओर से राष्ट्रपति को विलंब में मामला प्रस्तुत करना था। श्री यादव इस विलंब का लाभ नहीं उठा सकते और इसके प्रतिरिक्त वे इस विलंब को अपने कायदे के लिए पर्याप्त करने का प्रयास कर चुके हैं।

8. अब आयोग की उसका राय के लिए निर्देश प्रस्तुतों को विचार में लिया जाए। पटना उच्च न्यायालय ने श्री राम गण्य यादव को 1951 के अधिनियम की धारा 123(2) के अवधि के प्रमाण अनुचित प्रधाव के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। भ्रष्ट आचरण “अत्यं पर वलात् कद्या” कहा है जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत ही नहीं है यद्कि उसमें यह भी संवेदन किया है कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें दो भूत संभव हों, जिसमें कि श्री राम गण्य यादव को संवेदन का लाभ दिया जा सके। न्यायालय भ्रष्ट आचरण के आरोप के संबंध में प्रदृष्ट के ठीक-ठीक मामलों को ही प्रहृण करने हैं और आरोप को संवादीों पर पर सिद्ध किया जाने पर वह देते हैं। श्री यादव के विरुद्ध वृथ पर वलात् कद्यों का सिद्ध आरोप एक वहुत ही गंभीर आरोप है। वृथ पर वलात् कद्यों का उद्देश्य निवारन प्रक्रिया को लप्त कर देना भीर समाप्त कर देना होता है। वृथ पर वलात् कद्या एक धृपित अपराध है। अृथ पर वलात् कद्यों करने वाला निकृष्ट कोटि का चोर है। वह दिया का पात्र नहीं है भारत उसे विधि प्रधान्ति 1951 के अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन उपर्युक्त अधिकार दें लिया जाहिए। अतः मेरी राय में श्री राम गण्य यादव को 30-10-1981 से (उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख) पूरे छह वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जाना चाहिए। कोई अन्य कार्रवाई, धारा 8(1) के उपर्युक्तों के मूल उद्देश्य को ही प्रस्तुत कर देंगी और उस धारा के उपर्युक्तों को निर्धारित बना देंगी। तब उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को अपनी राय प्रस्तुत करता है कि श्री राम गण्य यादव को 30-10-1984 में पूरे छह वर्ष की अवधि के लिए निरहित किया जाए।

9. निष्कर्ष के रूप में यह कहना चाहिए है कि ऐसी प्रसादारण परिस्थिति में जो इस मामले में उपर्युक्त हुई है, अत्यं पर वृथ पर वलात् कद्या करने वाला अक्तिल लगातार तीन सावारण निवारन लड़न में समर्पण करता है, उपर्युक्त नहीं हुई होती यदि वे 1973 में विधि को उदार न बनाया गया होता। वर्ष 1975 में विधि को उदार बनाए जाने से पूर्व, कोई अपित और भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया, है 1951 के अधिनियम की धारा 99 के अधीन नारेंद्र द्वारा उन तारीख से उपर्युक्त आदेश प्रधावों द्वारा होता है, छह वर्ष की अवधि के लिए भ्रष्ट करता होता है जाता। तथापि, यह ऐसी सिर्जना के हटाए जाने या ऐसी निर्धारित की अवधि को कम किए जाने के लिए निवारन प्रधान्ति का पास वा लक्षण था। निवारन प्रधान्ति के प्रधावार भ्रष्ट आचरण, जो निवारन प्रधान्ति के लिए निरहित होता है, व्याप्त न होते हैं। व्याप्त न होते हैं,

इस प्रश्न के लिए बहुत कम गुजाइश रह जाती है कि यदि किसी ऐसे अकिस को जिसे किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, निर्वाचित न किया जाए। यदि कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ हैं तो उन्हें निर्वाचित हटाने या निर्वाचित की अवधि को कम करने के लिए उपयोग में साया जा सकता है। अब वर्ष 1975 के संप्रोत्तरों के पूर्व जो स्थिति विषयमान थी उस वर्ष से लाते के प्राप्ति पर गंभीरतापूर्वक विवार की आवश्यकता है।

६. एकट सूर्य परिषासी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली,

१२ जून, १९९०

[फा. सं. ७(२७)/९०-वि.-II]  
ची. एस. रमावेदी, सचिव

### MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1990

S.O. 547(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

#### ORDER

Whereas the election of Shri Ram Sharan Yadav (hereinafter referred to as the "returned candidate"), a returned candidate from 241-Goh Assembly Constituency in the State of Bihar at the General Election to the Legislative Assembly of Bihar held in June, 1977 was set aside by the Patna High Court on 10th April, 1980 on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practice specified in clause (2) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the said Act");

And whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court stayed the operation of the High Court's Order on 25th April, 1980;

And whereas the Supreme Court subsequently dismissed the appeal and also vacated the stay order on 30th October, 1984;

And whereas the case of the returned candidate was submitted by the Secretary, Bihar Legislative Assembly to the President on 19th March, 1990 in terms of sub-section (1) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section and, if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of six years

to be reckoned from 30th October, 1984 i.e. the date of the judgment of the Supreme Court;

Now, therefore, I, R. VENKATARAMAN, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from 30th October, 1984.

Rashtrapati Bhawan,  
New Delhi,  
the 3rd July, 1990.

PRESIDENT OF INDIA.

#### ANNEXURE BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re : Disqualification of Shri Ram Sharan Yadav elected to the Bihar Legislative Assembly at the General Election held in 1977.

#### OPINION

1.1 This is a reference from the President of India under section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the 1951-Act). It was made on 27-3-1990 in pursuance of a report dated 19-3-1990 under the said section by the Secretary, Bihar Legislative Assembly [specified authority under that section] and it is for seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Ram Sharan Yadav elected to the Bihar Legislative Assembly at the General Election held in 1977, should be disqualified and, if so, for what period.

1.2 Shri Ram Sharan Yadav's election to the Bihar Legislative Assembly from 241-Goh Assembly Constituency at the General Election held in June, 1977 was set aside by the Patna High Court by its Order, dated 10-4-1980 on the ground that he committed corrupt practice under section 123(2) [undue influence] at 79-Bhurkunda booth.

2.1 The following extract from the Judgment of the Patna High Court brings out clearly the details of the said corrupt practice committed by Shri Ram Sharan Yadav :

"Thus I have examined and discussed above the oral and documentary evidence adduced by the parties with regard to 79-Bhurkunda booth, from which it is clear that there is abundance of reliable evidence on the record to prove the petitioner's case that on the date of poll, at about 11.30 a.m. Respondent No. 6 Ram Sharan Yadav had arrived at Bhurkunda Booth in his jeep and had enquired about the trend of the poll from his man, Ram Prasad Yadav of village Ibrahimpur, who told him that the poll at the booth was poor in his favour and thereupon Respondent No. 6, Ram Sharan Yadav, ordered his men and supporters, who were standing at the polling booth, to capture the booth by scaring away the voters and also to surround the booth and the petitioner, and, after giving the said order,

he left booth and thereafter his workers and supporters surrounded the booth and scared away the voters and prevented them from exercising their right of franchise and also surrounded the petitioner and held him up there, and the same is nowhere shaken by the meagre and unbelievable evidence adduced on behalf of Respondent No. 6 in this regard. Therefore, it is held that respondent No. 6 and his workers, with his consent, did commit the corrupt practice of undue influence at Biurkunda booth by interfering with the free exercise of the electoral rights of the voters to cast their votes according to their choice." [Thakur Muneshwar Nath Singh v. Shyam Nandan Misra and others—62 ELR p. 223, at page 233].

2.2 On appeal by Shri Ram Sharan Yadav, the Supreme Court granted by its Order, dated 25-4-1980, ex-parte stay, pending notice, in the following terms :

"In view of the impending assembly elections in the State of Bihar and on the facts and circumstances of this case we stay the operation of the High Court's Order but the petitioner's [i.e. Shri Ram Sharan Yadav's] participation in the next election will be subject to the final result of this appeal.

This stay order was confirmed by the Supreme Court on 6-5-1983, pending final disposal of the appeal. On 30-10-1984, the Supreme Court dismissed the appeal and also vacated the stay order. The Supreme Court observed :

"After a careful perusal and discussion of the evidence, we entirely agree with the conclusions arrived at by the High Court and hold that there is no reason to interfere with the judgment of the High Court so as to take a different view. In our opinion, it is not a case where two views were possible so that the appellant [Shri Ram Sharan Yadav] could be given benefit of doubt."

[Ram Sharan Yadav v. Thakur Muneshwar Nath Singh and others—AIR 1985 SC, p. 24 at p. 28].

2.3 As a result of the dismissal of appeal of Shri Ram Sharan Yadav and vacation of stay orders as aforesaid on 30-10-1984 by the Supreme Court, the Order of the Patna High Court finding Shri Ram Sharan Yadav guilty of corrupt practice took effect on that date. According to section 8A of the Representation of the People Act, 1951, the case of Shri Ram Sharan Yadav ought to have been submitted by the Secretary to the Bihar Legislative Assembly being the specified authority under that section "as soon as may be" after the said date. Sub-section (1) of the said section 8A reads thus :

(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice, by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be,

after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period :

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect."

The period of six years, referred to in this proviso to the sub-section will be expiring in October, 1990. There has thus been an inordinate delay on the part of Secretary of the Bihar Legislative Assembly. This aspect of the matter may be inquired into separately and appropriate remedial measures by way of introducing a system of periodical submission of returns as to pending cases by authorities under the said section 8A to the President's Secretariat or to the Election Commission and reminders with respect thereto, can be considered for preventing, the recurrence of a similar situation in future.

3.1 Within a few days after the receipt of the present reference by the Commission, the Commission issued a notice on 4-4-1990 to Shri Ram Sharan Yadav to appear before it personally or through a duly authorised counsel on 17-4-1990, as the Commission, as a matter of consistent policy and practice, affords, for compliance with the rules of natural justice, an opportunity of personal hearing to the person affected in reference cases under section 8A of the 1951-Act.

3.2 Shri Yadav appeared before the Commission on 17-4-1990 and prayed for adjournment of the hearing by two months. He submitted that he received the Commission's notice only on the previous day, i.e. 16-4-1990, and that he wanted sufficient time for raising funds for engagement of a counsel and for engaging a counsel. In order to give him a reasonable opportunity, the hearing was adjourned by one month to 16-5-1990.

3.3 Shri Yadav filed written submission on 15-5-1990 and on 16-5-1990, he appeared before the Commission and again prayed for adjournment of the hearing to 6-5-1990 on the ground that the counsel he proposed to engage was busy in some important matters before the Patna High Court. The Commission again accepted his prayer and adjourned the hearing to 26-5-1990.

3.4 Shri Yadav again appeared before the Commission on 26-5-1990. He was represented by Shri Krishan Prasad Singh, Senior Advocate, who was assisted by Shri Udit Narain Singh and Shri Arvind Ujjawal, Advocates.

4. In the written submissions filed on 15-5-1990, Shri Ram Sharan Yadav has stated that after the Judgment of the Patna High Court in the year 1980, he fought three elections from the same 241-Goh Assembly constituency and that he was declared elected in two of those election, i.e. in 1980 and 1990. He also contended that the Election Court did not accept any order under section 99 of the Repre-

sentation of the People Act, 1951 on the basis of which he could be disqualified under section 8A of the Act. He has also urged that he was found guilty of corrupt practice on technical ground under the term "implied consent" and that the Supreme Court took a lenient view while dismissing his appeal because the Supreme Court did not award any costs against him. Shri Yadav also pointed out that thirteen years have elapsed from the election held on 19-6-1977 and that the maximum period of disqualification of six years under section 8A of the Representation of the People Act, 1951 would also be expiring in the month of October 1990. He has, accordingly, requested that the Commission might be pleased to drop the proceedings.

5.1 At the hearing held on 26-5-1990, Shri K. P. Singh, Senior Advocate, supplemented some of the written submissions made by Shri Yadav and also made certain additional submission. With regard to the contest by Shri Ram Sharan Yadav from the same Goh Assembly constituency in 1980, 1985 and 1990, Shri K. P. Singh, Sr. Advocate pointed out that when Shri Yadav contested the election in 1985, an objection was raised with regard to his nomination in the ground that he stood disqualified because by that time the Supreme Court had dismissed his appeal and that the said objection was over-ruled by the Returning Officer and that no question was thereafter raised by any one with regard to Shri Yadav's disqualification. He urged that in view thereof, Shri Yadav was under the bona fide belief that no disqualification had been imposed upon him on the basis of the High Court's Order, dated 10-4-1980 or the Supreme Court's Order, dated 30-10-1984. In this connection, Shri Singh referred to the provisions of sub-section (1) of section 8A of the 1951-Act which envisage the case of every person found guilty of a corrupt practice being submitted to the President "as soon as may be" after the order of the High Court or, as the case may be, the Supreme Court took effect. He submitted that the inordinate delay in the submission of Shri Yadav's case to the President was a sufficient ground for not imposing any disqualification on Shri Yadav who had all along been acting under the bona fide belief that he was not disqualified and spent a lot of energy, time, labour and money in contesting the election in 1985 and particularly 1990. Shri Singh also submitted that under the provision of section 8A(1) of the 1951-Act, the maximum period for which the disqualification could be imposed was six years from the date on which the order of the Court finding a person guilty of corrupt practice took effect and that if the case had been submitted to the President in time and decided by him, the period of disqualification imposed, if any, on Shri Yadav would, in all probability, have expired by now. He reiterated the submission that the Supreme Court had taken a lenient view inasmuch as that Court had not awarded any costs against Shri Yadav and that therefore, the Commission should also take a lenient view in the matter.

5.2 Lastly, Shri Singh referred to the decree, dated 30-10-84, of the Supreme Court and mentioned that the decree seemed to indicate that the Supreme Court stayed the operation of the High Courts' order on 6-5-1983. While conceding that he was not in possession of any document to show whether any ad interim stay order had been passed by the

Supreme Court earlier, he contended that if the stay order was granted on 6-5-1983 by the Supreme Court, then the High Court's Order remained in operation for more than three years and if that period was also taken into account the maximum period of six years for which the disqualification could be imposed was already over.

6.1 I have carefully considered the written submissions of Shri Ram Sharan Yadav as also the submissions made on his behalf by Shri K. P. Singh, Senior Advocate at the hearing held on 26-5-1990.

6.2 First of all, I may dispose of two points of a "technical" nature—one made in the written submissions by Shri Yadav and the other made by Shri K. P. Singh, Senior Advocate.

6.3 In the written submissions, Shri Yadav has contended that the Supreme Court did not pass any order under section 99 of the Representation of the People Act, 1951 on the basis of which he could be disqualified under section 8A of the 1951-Act. This point was rightly not taken up by his Counsel, Shri K. P. Singh, Senior Advocate, at the hearing on 26-5-1990. The Patna High Court found Shri Yadav guilty of corrupt practice and made an order to that effect under section 99 of the 1951-Act. This Order of the Patna High Court was stayed by the Supreme Court and the said stay order was vacated by the Supreme Court by its Order dated 30-10-1984 and thereupon Order made by the Patna High Court under section 99 of the 1951-Act took effect.

6.3 The "technical" point made by Shri K. P. Singh, Senior Advocate, relates to the stay of the High Court's Order by the Supreme Court and its effect on the period of disqualification. According to the records of the Commission, the Supreme Court stayed the High Court's Order by an ad interim order on 25-4-1980. However, even if the stay had been granted for the first time by the Court on 6-5-1983, that would not have altered the position in any material respect because section 116B(3) of the 1951-Act clearly states, *inter alia*, that when the operation of an Order of the High Court is stayed by the Supreme Court, the Order of the High Court "shall be deemed never to have taken effect". Thus, even if the High Court's Order, dated 10-4-1980 was stayed by the Supreme Court on 6-5-1983, the High Court's Order would be deemed never to have taken effect once it was stayed by the Supreme Court and the High Court's Order, dated 10-4-1980, would be deemed to have taken effect only with effect from 30-10-1984 when the Supreme Court dismissed the appeal and confirmed the High Court's Order and vacated the stay. In view of the above, the period of six years specified in section 8A(1) of the 1951-Act has to be reckoned in the present case from 30-10-1984.

7.1 As regards the written submission by Shri Yadav that he was found guilty of corrupt practice on technical ground under the term "implied consent", it is sufficient to refer to the conclusion of the Supreme Court that this is not a case where two views are possible so that Shri Yadav could be given the benefit of doubt.

7.2 The written submission by Shri Yadav, which has been reiterated by Shri K. P. Singh, Senior

Advocate, namely, that the Supreme Court took a lenient view by not awarding any costs against Shri Yadav, may now be considered. The Supreme Court has not spelt out in its Judgment the reasons for which the Court was pleased to dismiss the appeal without any order as to costs. However, the Supreme Court has clearly and unambiguously upheld the Judgment of the High Court. Further, in the opening portion of the Judgment, the Supreme Court itself has observed that the charge of corrupt practice "if proved, entails a very heavy penalty in the form of disqualification." This observation may give a clue as to why the Supreme Court chose not to award any costs against Shri Yadav. In any case, the mere non-awarding of the costs by the Supreme Court can hardly be considered as a mitigating circumstance in favour of Shri Yadav.

7.3 Lastly, I may deal with the submissions relating to the inordinate delay in the submission of the case by the Secretary to the Bihar Legislative Assembly to the President of India and the other submissions connected therewith. It is true that there has been inordinate delay on the part of the Secretary in submitting the case of Shri Yadav to the President. According to section 8A(1) of the 1951-Act, the Secretary is, no doubt, required to submit the case without delay. But this obligation on the part of the Secretary cannot be read as providing for a period of limitation within which cases should be submitted. Further, Shri Yadav has taken full advantage of this lapse on the part of the administrative machinery. If the case had been submitted to the President in time, in all probability, Shri Yadav would have been disqualified towards the end of 1984 or in the early part of 1985. If that disqualification had been imposed upon him for full term of six years as envisaged in the said section 8A(1), he would not have been able to contest the elections either in 1985 or in 1990. Even when he obtained ex parte stay in 1980 and contested the 1980-election, he did so with the full awareness that his participation in the election would be subject to the final result of the appeal before the Supreme Court. He contested the 1980-election with the Democlean Sword of disqualification on his head as this position was made clear by the Supreme Court in its ex parte stay order, dated 25-4-1980. When he contested the election in 1985, an objection was raised on the basis of the final Order of the Supreme Court and if the objection was rejected by the Returning Officer, it was only because no order of disqualification was made against Shri Yadav by that time. Having regard to the fact that Shri Yadav fought his case before the Patna High Court and before the Supreme Court over a period of more than five years and having regard to the orders passed by the Supreme Court in this case, it would be difficult to believe that Shri Yadav was, at any time, throughout the relevant period unaware of the possibility of his becoming liable to disqualification. It is, therefore, not unreasonable to conclude that just as he contested the 1980-election taking the risks involved, he contested the 1985 and 1990 elections taking the risks involved. If he could contest the 1985 and the 1990 elections, it was only because of the delay on the part of the Secretary,

Bihar Legislative Assembly in submitting the case to the President. Shri Yadav cannot be permitted to take advantage of this delay, more so when he tried to convert this delay to his own advantage.

8. The questions referred to the Commission for its opinion may now be taken up. The Patna High Court found Shri Ram Sharan Yadav guilty of corrupt practice of undue influence within the meaning of section 123(2) of the 1951-Act. The corrupt practice is by way of "booth-capture". As already mentioned, the Supreme Court has not only agreed with the conclusions arrived at by the High Court but has also observed that this is not a case where two views were possible so that Shri Ram Sharan Yadav could be given benefit of doubt. The Courts adopt very strict standards of proof in relation to a charge of corrupt practice and insist upon the charge being proved beyond any shadow of doubt. The charge of booth-capturing proved against Shri Yadav is a very grave charge. A booth-capturer's aim is to under-cut and undermine the electoral process. Booth-capture is a heinous offence. A booth-capturer is a thief of the worst type. He deserves no leniency and should be visited with the maximum penalty provided under the law, viz. section 8A(1) of the 1951-Act. Therefore, I am of the view that Shri Ram Sharan Yadav should be disqualified for the full period of six years reckoned from 30-10-1984 (the date of the Order of the Supreme Court). Any other course of action might defeat the very object underlying the provisions of section 8A and render the provisions of that section nugatory. Accordingly, I hereby tender my opinion to the President that Shri Ram Sharan Yadav be disqualified.

9. In conclusion, I may mention that the extraordinary situation which has arisen in this case, namely, of a booth-capturer being able to contest three successive General Elections would not have arisen if the law had not been liberalised in 1975. Before the liberalisation of the law in 1975, a person found guilty of corrupt practice by an order under section 99 of the 1951-Act became automatically disqualified for a period of six years from the date on which that order took effect. He could, however, approach the Election Commission for removing such disqualification or for reducing the period of such disqualification. Having regard to the nature of corrupt practices provided in the Act, there is little scope for any question as to a person found guilty of any corrupt practice not being liable to disqualification. If there are any mitigating circumstances, those could be availed of for removing the disqualification or reducing the period of disqualification. Hence the question of reverting to the position as it obtained before the 1975-amendments deserves serious consideration.

New Delhi, the  
12th June, 1990.

R. V. S. PERI SASTRI, Chief Election Commissioner  
of India.

[F. No. 7(27)90-Leg. II]  
V. S. RAMA DEVI, Secy.